

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1589

जिसका उत्तर मंगलवार, 02 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

राजस्थान में भारी उद्योग

1589. श्री राहुल कस्वां:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजस्थान में कार्य कर रहे भारी उद्योगों और लोक उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और
(ख) पिछले कई वर्षों के दौरान ऐसे उद्योगों/उद्यमों को वार्षिक कारोबार क्या है तथा इन्हें हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है एवं देश की अर्थव्यवस्था पर इनका क्या प्रभाव है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्धेश्वर)

(क): चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए देश के विभिन्न राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे भारी उद्योगों और लोक उद्यमों का इस विभाग में कोई केन्द्रीकृत आंकडा नहीं रखा जाता है। भारी उद्योग विभाग की भूमिका इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) तक सीमित है। इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय राजस्थान में हैं। ये उद्यम सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल), राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स (इंडिया) लिमिटेड (आरईआईएल), इन्डूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) हैं।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसमें इस राज्य में स्थित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं, के वार्षिक कारोबार तथा लाभ-हानि का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 2012-13 के खण्ड। के विवरण संख्या 15 और 3 में उपलब्ध है जिसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर पहले ही दिनांक 20 फरवरी, 2014 को रखा जा चुका है।

उपर्युक्त सर्वेक्षण के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपर्युक्त 4 उद्यमों के वार्षिक कारोबार और लाभ-हानि का ब्यौरा निम्नवत है:-

वार्षिक कारोबार

₹ लाख में

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	2012-13	2011-12	2010-11
एसएसएल	1666	1893	991
एचएसएल	873	962	1325
आरईआईएल	23962	23135	13314
आईएलके	17206	19265	25102

लाभ/हानि

₹ लाख में

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	2012-13	2011-12	2010-11
एसएसएल	30	106	-413
एचएसएल	74	22	-49
आरईआईएल	2637	1862	503
आईएलके	-5409	-6769	-3656

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम रोजगार उपलब्ध कराते हैं तथा विभिन्न करों के रूप में राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।
